खण्ड–8, अंक–1, वर्ष–2020
D.O.I.: 10.22445/avsp.v8i1.16

भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव का क्षेत्रीय विश्लेषण

प्रीति पन्त

वाणिज्य विभाग, बी.एस.एन.वी. पी.जी. कॉलेज, लखनऊ–226 001, उ.प्र., भारत

प्राप्ति तिथि–30.09.2020, स्वीकृति तिथि–16.11.2020

सार– कोविड–19 की हालिया वैश्विक महामारी ने स्वास्थ्य संकट के अतिरिक्त कई देशों में विनाशकारी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संकट उत्पन्न किये हैं। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए एक सुधारात्मक उपाय के रूप में लॉकडाउन का अनुसरण किया। इसके परिणामस्वरूप एलएंडटी, भारत फोर्ज, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आदित्य बिड़ला समूह, भेल और टाटा मोटर्स जैसी प्रमुख कंपनियों के औद्योगिक संचालन में अस्थायी रूप से निलंबन या बहुत कमी आई। इसने अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है जिससे अपेक्षित हानि प्रतिदिन 32,000 करोड़ रुपये (4.5 अरब अमेरिकी डॉलर) है। पूर्ण लॉकडाउन के अंतर्गत, भारत की $ 2.8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का मात्र एक चौथाई से भी कम हिस्सा कार्यात्मक था। इस दौरान भारतीय शेयर बाजारों में भी बड़ी गिरावट अंकित हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के समग्र आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इस संदर्भ में भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने और युवा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख जोर दिया जा रहा है। यह शोध–पत्र भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 के प्रभावों का विश्लेषण करने का एक प्रयास है। इस संदर्भ में क्षेत्रीय विश्लेषण पर विशेष बल दिया गया है तथा महामारी का मुकाबला करने की रणनीति के रूप में लॉकडाउन के सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोण को उजागर करने का भी प्रयास किया गया है।

बीज शब्द– कोविड–19, महामारी, भारतीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय विश्लेषण, लॉकडाउन

Sectoral Aanalysis of Impact of COVID-19 Pandemic on Indian Economy

Preeti Pant

Department of Commerce, BSNVPG College, Lucknow-226 001, U.P., India

Abstract- The recent global pandemic COVID-19 besides health crisis, has also created devastating social, economic and political crises for many countries. Indian Government and other strict measures followed lockdown as a remedial measure to fight against the coronavirus outbreak. It resulted in temporarily suspension or significantly reduction in industrial operations of major companies in India like, L&T, Bharat Forge, UltraTech Cement, Grasim Industries, Aditya Birla Group, BHEL & Tata Motors. It severely affected the economy with an expected loss of Rs 32,000 crore ($ 4.5 billion) every day. Under complete lockdown, less than a quarter of India's $ 2.8 trillion economic movement was functional. Indian stock markets are also witnessing major breakthrough during this period. Prime Minister Mr. Narendra Modi has announced an overall economic package of Rs 20 lakh crore in this context. Major emphasis is on making India as a self-reliant nation and to promote young startups. This paper is an attempt to analyze the impact of COVID-19 on the Indian economy. Special emphasis has been made on the sectoral analysis in this context and an attempt has been made to highlight the socio-economic perspectives of the lockdown as a strategy to combat the effects of pandemic.

Key words- COVID 19, Pandemic, Indian economy, Sectoral Analysis, Lockdown

Corresponding Author: preetipant.2311@gmail.com

1. परिचय

यह बहुत आश्चर्य बात है कि परमाणु युद्ध एवं एसट्राइड हिट के इस युग में हम विषाणु जनित महामारियों से मानवता को बचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। विशेषज्ञों के एक पक्ष का मत यह है कि प्रति सौ वर्षों के अंतराल पर एक बार महामारी वैश्विक स्तर पर फैलती है और जनसंख्या में एक सन्तुलन बनाने का प्रयास करती है। इस सोच के पीछे राबर्ट माल्थुस का जनसंख्या सिद्धांत है, जो उन्होंने 1798 मे दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि मानव जनसंख्या नियन्त्रण के लिये स्वयं प्रयास नहीं करते हैं तो प्रकृति स्वयं इस सन्तुलन को बनाने का प्रयास करती है। यह प्राकृतिक प्रयास कहलाते हैं और मानवता के लिए सदैव विध्वंसकारी होते हैं। वहीं दूसरी ओर एक पक्ष ऐसा भी है जो इस बात से सहमत नहीं है। इस पक्ष के अनुसरणकर्ता इस बात को सिरे से नकारते हुए इन महामारियों को प्राकृतिक घटना की श्रेणी में न रखने के पक्षधर हैं। इस सोच के पीछे डब्लू.एच.ओ. की महामारी की वह परिभाषा है जिसमें इसे बैक्टिरिया या वायरस से जनित बताया गया है। यह बैक्टीरिया या वायरस मनुष्यों की रोग–प्रतिरोधक क्षमता पर आक्रमण करता है, जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है वे इसके दुष्परिणामों से ग्रसित हो जाते हैं। आधुनिक महामारियों की सबसे बड़ी विशेषता परस्पर विरोधी सत्यों का तीव्रगामी संचार व वैज्ञानिक जवाबी प्रतिक्रियाओं द्वारा विशाल दूरी पर तेजी से संवहन है। इसलिए कुछ हद तक यह आश्चर्यजनक है कि इन महामारियों ने जहाँ एक ओर पूरे इतिहास में मानवता के लिए संकट उत्पन्न किया है, वहीं दूसरी ओर कोविड–19 ने सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान किया है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग की किसी भी महामारी की तुलना में वैश्विक स्तर पर सबसे कम मौतों के लिए जिम्मेदार होते हुए भी अब तक की सबसे महंगी महामारी साबित हुई है (**सारिणी–1**)।

अध्ययनों से पता चला है कि 1940 से 2004 के बीच 300 से अधिक नए संक्रामक रोग सामने आए, जबकि सभी उभरती हुई संक्रामक बीमारियों में इबोला, एच.आई.वी., एवियन फ्लू, सार्स और कोविड–19 शामिल हैं।[1] कोविड–19 एक संक्रामक बीमारी है जिसका

सारिणी–1: भयावह महामारियों का वैश्विक इतिहास

महामारी की अवधि	महामारी	पहला पंजीकृत मामला	वैष्विक जनसंख्या (मिलियन व्यक्ति)	संक्रमित (व्यक्ति)	मृत्यु (व्यक्ति)	संक्रमित व्यक्ति (वैष्विक जनसंख्या का %)	मृत्यु (वैष्विक जनसंख्या का %)
1347–1351	प्लेग	पूर्व एशिया	350	303,030,303	200,000,000	86.60	57.14
1918–1920	इंफ्लुएंजा महामारीः स्पेनिश फ्लू	फोर्ट रिले, कान्सास	1860	500,000,000	50,000,000	26.90	2.69
1957–1958	इंफ्लुएंजा महामारीः एशियाई फ्लू	सिंगापुर	2873	164,179,104	1,100,000	5.70	0.04
1961–1975	हैजा	इंडोनेशिया	3072	400,000	4,000	0.00	0.00
1968–1970	इंफ्लुएंजा महामारीः हांगकांग फ्लू	हांगकांग	3532	149,253,731	1,000,000	4.20	0.03
1981 से अब तक	एच.आई.वी. एड्स	किंशासा	4511	76,000,000	32,000,000	1.70	0.71
2002–2004	सार्स–कोव	फोशान	6272	8,000	800	0.00	0.00
2009–2010	इंफ्लुएंजा महामारीः स्वाइन फ्लू	वेराक्रूज	6839	60,800,000	18,449	0.90	0.00
2012–2019	मार्स–कोव	सऊदी अरब	7085	2,494	858	0.00	0.00
दिसंबर 2019 से अब तक'	सार्स–कोव–2	वुहान	7673	6,88,45,368	15,70,304	0.89	0.13

स्रोत– https://knoema.com/ , 11 दिसम्बर, 2020 तक

मुख्य कारण श्वसन सिंड्रोम है। इसका प्रथम पंजीकृत मामला चीन के वुहान प्रदेश में दिसम्बर, 2019 में पाया गया था। 11 मार्च, 2020 को डब्ल्यू.एच.ओ. ने कोविड–19 को महामारी घोषित किया। इससे अब तक वैश्विक स्तर पर 190 राष्ट्रों में कुल 68.8 मिलियन से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, लगभग 67.27 मिलियन लोग ठीक हो चुके हैं और तकरीबन 1.5 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है (11 दिसम्बर, 2020 तक)।[2] इस महामारी को कोरोनावायरस, कोरोना, कोविड–19, नोवेल कोरोना वायरस इत्यादि नाम दिये गये हैं।

भारत में पहला पंजीकृत संक्रमित 30 जनवरी, 2020 को केरला मे पाया गया था। इसके पश्चात् चीन के वुहान से वापस आये तीन छात्रों में फरवरी में कोविड पाया गया था। मार्च मे संक्रमण की दर में तेजी से वृद्धि हुई। संक्रमण से भारत मे पहली मृत्यु 12 मार्च, 2020 को हुई। भारत में कुल 9.83 मिलियन व्यक्ति कोविड से संक्रमित, 9.32 मिलियन व्यक्ति स्वस्थ होकर अस्पताल से मुक्त कर दिये गये, 1,43,000 (एक लाख तेंतालिस हजार) व्यक्ति कोविड–19 महामारी से मृत हो चुके हैं (11 दिसम्बर 2020 तक अद्यतन)।[3]

2. कोविड–19 के प्रभावों को कम करने के लिए सरकार की रणनीति

पूर्व में इसी प्रकार की महामारियों के रोकथाम के लिए किये गये प्रयासों के आधार पर कोविड–19 पर नियंत्रण पाने के तीन उपाय हैं– सामूहिक टीकाकरण, झुन्ड उन्मुक्ति (हर्ड इम्यूनिटी) व सामाजिक दूरी। इन उपायों में से सामूहिक टीकाकरण व हर्ड इम्यूनिटी दोनों ही अल्पकाल में सम्भव नहीं है। अतः सरकारों ने सामाजिक दूरी के उपाय को चुना। इसे सुनिश्चित कराने के लिये लॉकडाउन की रणनीति को अपनाया गया। इसके अंतर्गत आवश्यकतानुसार अनेक क्रियाओं पर प्रतिबन्ध लगाये गये, इन प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न दिशा–निर्देश जारी किये। सर्वप्रथम चीन ने लॉकडाउन रणनीति अपनायी, जिसे जल्द ही वियतनाम व पूर्वी एशिया के अन्य राष्ट्रों ने भी अपनाया। यह विश्व का अभी तक का सबसे बड़ा लॉकडाउन साबित हुआ है। 26 मार्च, 2020 को विश्व के लगभग 1.7 बिलियन लोग किसी न किसी प्रकार के लॉकडाउन से प्रभावित थे। कोविड–19 महामारी की विभीषिका इस बात से आंकी जा सकती है कि अप्रैल, 2020 में लॉकडाउन से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या बढकर कुल 3.9 बिलियन हो गयी, जो कि वैश्विक जनसंख्या का लगभग आधा भाग से अधिक था। अप्रैल माह के अन्त तक यह संख्या 300 मिलियन पहुँच गयी जो कुल वैश्विक जनसंख्या का लगभग 90% थी।[4] अमेरिका जैसी विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था भी कोविड–19 के दुष्परिणामों से तहस–नहस हो गयी। चीन, फिजी, फ्रांस, भारत, इण्डोनेशिया, आयरलैण्ड, इटली, मलेशिया, नामीबिया, न्यूजीलैण्ड, फिलीपीन्स, सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका वे प्रमुख राष्ट्र हैं जिन्होंने लॉकडाउन को प्रभावी रणनीति के रूप में अपनाया। इसमें कुछ राष्ट्रों का मत यह भी रहा कि लॉकडाउन लगाना कोविड–19 जैसी वायरस जनित महामारी से लड़ने के लिए प्रभावी नहीं है। स्वीडन में उच्च शिक्षण संस्थाओं को बन्द रखा गया जबकि प्राथमिक पाठशालाओं, भोजनालयों इत्यादि को बिना प्रतिबन्ध खोला गया। वृद्ध नागरिकों को बाहर निकलने से मना किया गया। इसके पीछे की सोच वृद्धों में बच्चों की तुलना में रोग–प्रतिरोधक क्षमता का कम होना है। एशिया महाद्वीप में जापान व दक्षिणी कोरिया ने लॉकडाउन नहीं लगाया था। अमेरिका और ब्राजील जैसे राष्ट्रों ने लॉकडाउन से सम्बन्धित कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं दिये, मात्र "घर पर रहने" को कहा गया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लॉकडाउन ने भले ही कोविड–19 से संक्रमण की गति को कम करके मृत्यु दर को कम किया है, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से लॉकडाउन के फलस्वरूप बेरोजगारी, निर्धनता, आत्महत्या इत्यादि समस्याओं को भी उत्पन्न किया है। इसमें इस बात का आंकलन करना कठिन है कि इन दोनों में से कौन सी हानि अधिक विनाशकारी एवं विध्वसंकारी है? राजनैतिक विशेषज्ञों के एक समूह का मत यह भी है कि लॉकडाउन लगाने के सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार ने अपनी शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण करते हुए राज्यों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार प्रतिबन्ध लगाने या उनमें ढील देने की स्वतन्त्रता प्रदान की। यदि यह दशा इसी प्रकार चलती रही तो भविष्य में राज्य सरकारें इस शक्ति को चिरकालीन शक्ति बनाकर इसका दुरुपयोग न करें।

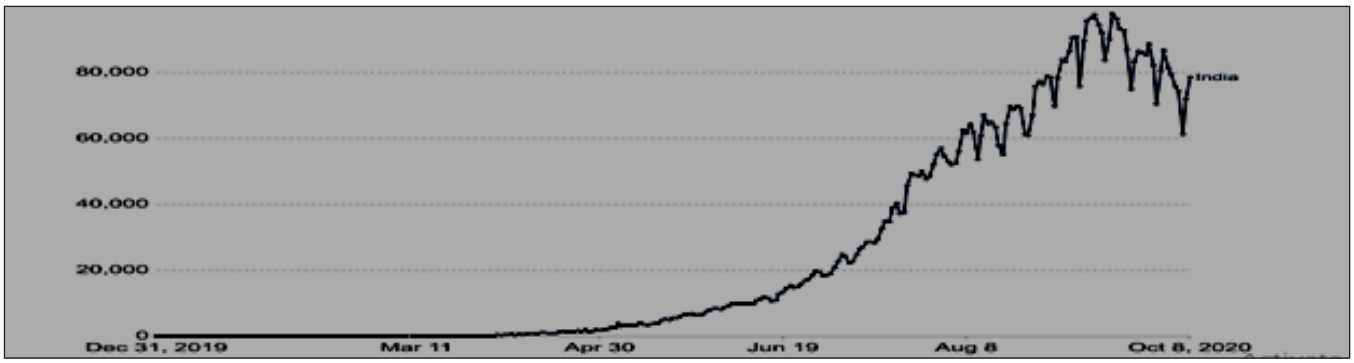

चित्र–1: कोविड–19 से भारत मे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या
स्रोत–यूरोपियन सेन्टर फॉर डिजीस प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल

भारत के सन्दर्भ मे लॉकडाउन को सरकार ने कई चरणों में लगाया व सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए गये थे। कई राज्यों ने निर्देशों का कठोरता से अनुपालन करने के उद्देश्य से धारा–144 भी लगायी थी। इस श्रृंखला में किसी भी प्रकार के धर्मिक, राजनैतिक, पारिवारिक समारोहों पर रोक थी जिसे बाद में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताकर समाजिक दूरी के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया। इस कड़ी में लोगों को तरह–तरह से जागरूक भी करने का प्रयास किया गया। **"आरोग्य सेतु"** एप के माध्यम से लोगों को अपने नजदीकी क्षेत्रों में संक्रमित लोगों की जानकारी प्राप्त हुयी। लोगों मे निराशावादी दशा में उत्साह व ऊर्जा के संचार के उद्देश्य से प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने समय–समय पर अपने उद्बोधन से राष्ट्र को सम्बोधित किया। प्रधानमंत्री ने जनमानस से कोरोना योद्धाओं (पुलिस, डाक्टर, नर्स इत्यादि) का सम्मान करने व यथासम्भव अपने स्थान पर बने रहने की अपील की। साधारण जनता को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे स्वयं इस संकट काल में अपना एवं अपने सगे सम्बन्धियों का ध्यान रखे। भारत सरकार ने लॉकडाउन को सुनियोजित तरह से लागू करने हेतु पहले एक प्रायोजिक परियोजना के तहत 22 मार्च 2020 को चौदह घण्टों के 'जनता कर्फ्यू' का आवाहन किया। इसके सफल परिणाम देखते हुए सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से कई चरणों मे लॉकडाउन किया (**सारिणी–2**)। लॉकडाउन मे सरकार ने कोरोना योद्धाओं के माध्यम से देशवासियों को मास्क, सामाजिक दूरी एवं रोग–प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के सम्बन्ध में जागरूक किया।

भारत सरकार ने 1 जून, 2020 से कई चरणों में सुनियोजित ढ़ंग से व्यवस्था को अनलॉक करना प्रारम्भ किया (**सारिणी–3**)। इसके पीछे सरकार की मंशा कोरोना के साथ युद्ध लड़ते हुए अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास है। लॉकडाउन में जहाँ अर्थव्यवस्था की गति को अचानक से धक्का लगा वहीं दूसरी ओर अनलॉक ने धीरे–धीरे इसे वापस पटरी पर लाने का प्रयास किया है।

इस महामारी ने निश्चित रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था को अधोपतन की ओर अग्रसर किया है और हाल के दशकों में विकसित हुए व्यापार स्वरूप को मौलिक रूप से परिवर्तित किया है। 1950 के दशक के पश्चात्, अन्य महामारियों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है, परन्तु कोविड–19 महामारी 2020 की वैश्विक मंदी के प्राथमिक चालक के रूप में अत्यधिक घातक साबित हुई है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन में 2020 में 6 से 7% की कमी का अनुमान है।[5]

सारिणी–2: लॉकडाउन के चरण

चरण	समय सीमा	रणनीति
I	25 मार्च से 14 अप्रैल	• क्षेत्रीय सीमाओं की सीलिंग • केवल आवश्यक सेवाओं के लिए लॉकडाउन मे छूट
II	15 अप्रैल से 3 मई	• लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध • सभी गैर–जरूरी गतिविधियाँ बंद • सार्वजनिक स्थान बंद
III	4-17 मई	• रेल, इंटरसिटी व बस सेवाएँ निलंबित • निजी कंपनियों में घर से काम
IV	18-31 मई	• सभी सार्वजनिक समारोहों (सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक)पर प्रतिबंध • सामाजिक दूरी • स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल बंद • आवश्यक आपूर्ति, किराने के स्टोर, फार्मा और बैंकों की सेवाएँ जारी

सारिणी–3: अनलॉक के चरण

चरण	समय सीमा	रणनीति
I	1 से 30 जून	शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्तरां को फिर से खोलने की अनुमति
II	1 से 31 जुलाई	राज्य सरकारों को सभी गतिविधियों पर उपयुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति लेकिन राज्य की सीमाएँ पर प्रतिबंध नहीं
III	1 से 31 अगस्त	रात मे कर्फ्यू और व्यायामशालाओं व योग केंद्रों को फिर से खोलने की अनुमति
IV	1 से 30 सितम्बर	मेट्रो रेल को चलाने की अनुमति
V	1 से 30 अक्टूबर	स्कूलों के लिए यदि संभव हो तो ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता, लेकिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 अक्टूबर से उन फैसलों को लेने मे छूट

3. कोविड–19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

कोविड–19 का पूर्ण आर्थिक परिणाम अभी तक स्पष्टतः ज्ञात नहीं है, परन्तु इस महामारी से भारतीय अर्थव्यवस्था का 5.9% संकुचन होने की आशंका है। यू.एन. रिपोर्ट के अनुसार भले ही इस तेजी को अर्थव्यवस्था पुनः प्राप्त कर ले परन्तु यह सदैव के लिये आय की हानि साबित होगा। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय चरम मंदी झेल रही है, और अभी तक महामारी का कोई समाधान नही हुआ है।[6] विकसित राष्ट्रों ने भी अपनी सकल घरेलू आय से राजकोषीय घाटे के 11% अधिक होने की आशंका व्यक्त की है। अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सी फिच व मूडी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में वृद्धि के घटकर 0.8% से 0.2% तक होने की आशंका जतायी है।[7] भारत सरकार के प्रमुख वित्तीय सलाहकार के अनुसार 2020–21 के वित्तीय वर्ष में भारत की सकल घरेलू आय की वृद्धि दर के नकारात्मक होने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था को इस संकुचन से उबारने के लिये राष्ट्र को लगभग 10 लाख करोड़ के बजट की आवश्यकता होगी।[8]

इस सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जी–20 राष्ट्रों में भारत की जी.डी.पी. की वृद्धि दर 1.9% के साथ सर्वाधिक होने का अनुमान है।[9] यह 1950 के पश्चात् का अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक बड़ा संकुचन होगा। आई.सी.आर.ए. रेटिंग एजेन्सी द्वारा 2020–21 में भारत की जी.डी.पी. में 11% की कमी का अनुमान है (जो कि पूर्व में 9.5% था)।[10] अप्रैल से जून 2020 में प्रथम तिमाही में जी.डी.पी. में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अनुमानिम वृद्धि दर में 23% की गिरावट दर्ज की गयी है।[11]

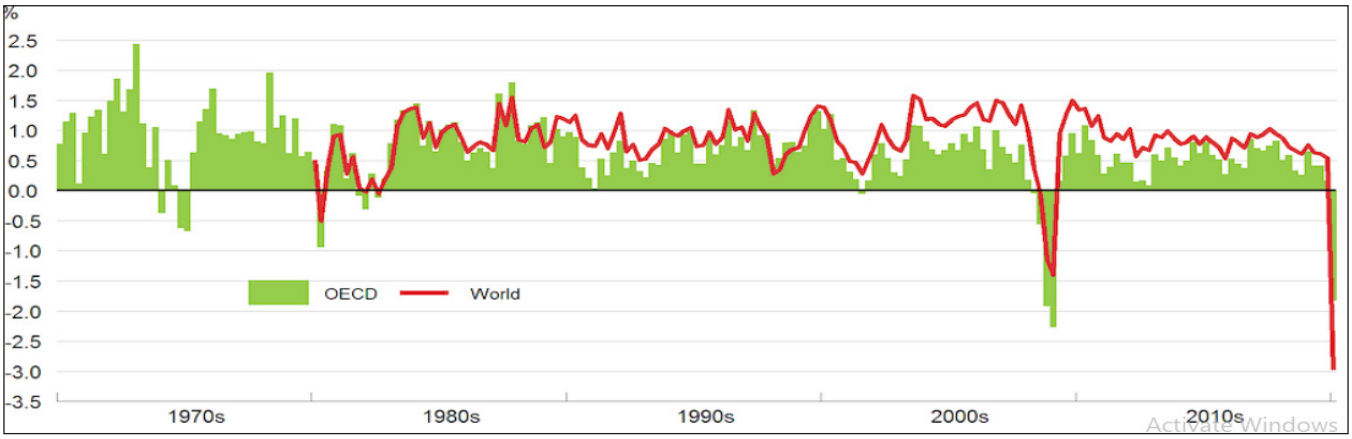

चित्र–2: कोविड–19 से वैश्विक गतिविधियों पर 2020 की पहली तिमाही में आई आकस्मिक गिरावट
स्रोत– ओ.ई.सी.डी. आउटलुक, 2020

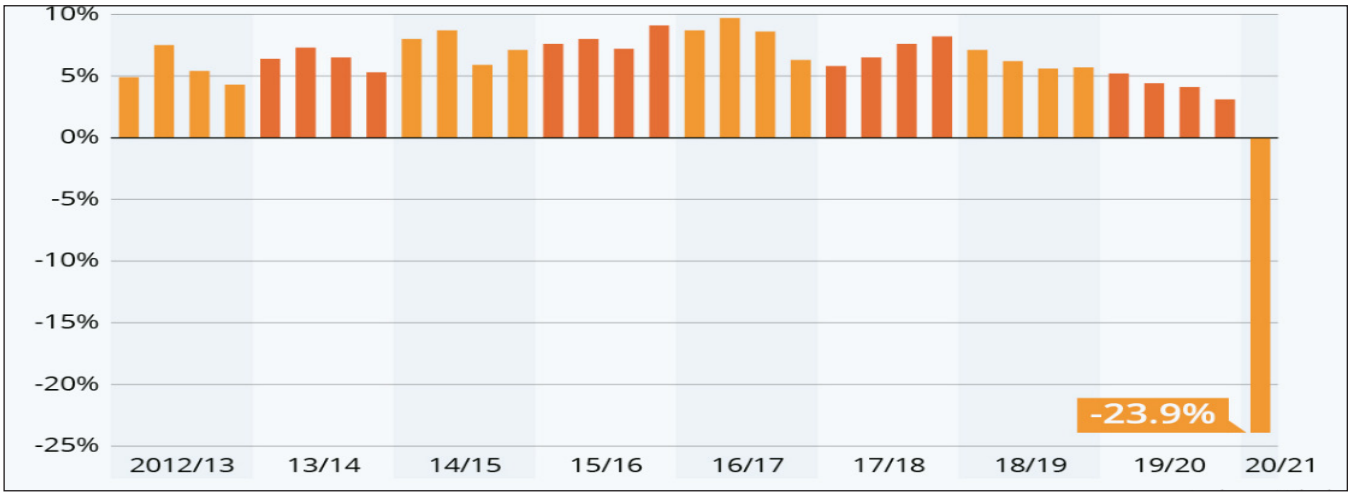

चित्र–3: भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न वित्तीय वर्षों की पहली तिमाही की जी.डी.पी. की तुलना
स्रोत– सांख्यिकी ओर कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

विश्व बैंक के अनुसार इस वर्ष भारत की जी.डी.पी. 9.6% संकुचित होने का अनुमान है।[12] कोविड-19 ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है (**सारिणी–4**)।

4. कृषि क्षेत्र पर प्रभाव

राष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सी क्रिसिल के अनुसार कृषि क्षेत्र में इस वर्ष भी 2.5% वृद्धि का अनुमान है जो इस बात की ओर इंगित करता है कि इस क्षेत्र पर, जो कि भारतीय जी.डी.पी. का 8.5% भाग है, कोविड–19 का अन्य क्षेत्रों की तरह बड़ा नकारात्मक प्रभाव नही पड़ा है।[13] लॉकडाउन में कृषि क्षेत्र को विशेष छूट प्रदान करने के कारण इस क्षेत्र पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हुआ परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से यह भी प्रभावित हुआ है। सबसे बड़ा प्रभाव आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान एवं प्रवासी मजदूरों की गृह वापसी का पड़ा। आपूर्ति श्रृंखला के इस व्यवधान ने जहाँ एक ओर कृषि क्षेत्र के इनपुट को प्रभावित किया वहीं दूसरी ओर कृषि उत्पादन की अंतिम उपभोक्ता तक पहुँच को भी प्रभावित किया। लॉकडाउन में भोजनालयों एवं कार्यक्रमों पर प्रतिबन्ध लगने से कृषि उत्पादों की मांग पर भी प्रभाव पड़ा, इसका सबसे बड़ा प्रभाव फूलवानी व बागबानी व्यवसाय पर पड़ा है। आई.एन.आई. फार्म के वित्त प्रमुख के हवाले से जनवरी से मई तक का समय बागबानी उद्योग में चोटी के निर्यात का समय होता है परन्तु आकस्मिक बन्दी ने इस उद्योग की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है और लगभग 80% का नुकसान किया है।[14] फूलबानी का व्यवसाय, जोकि प्रति वर्ष 20,000 करोड़ का था, को इस महामारी ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। अप्रैल व मई में इस उद्योग की बिक्री चरम सीमा पर होती है, अकेले बैंगलुरू ग्रामीण जिले में 2000 से अधिक कृषकों को लगभग 360 करोड़ का घाटा हुआ।[15] आपूर्ति श्रृंखला एवं यातायात में व्यवधान ने मार्च, 2020 के माह में विगत वर्ष के मार्च माह की तुलना में बिक्री को आधा कर दिया है।[16] इस सन्दर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कृषि क्षेत्र पर ऋण के बोझ को कम करने के उद्देश्य से 3 माह (31

सारिणी–4: भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 के प्रभाव का क्षेत्रीय विश्लेषण

क्षेत्र	**2017–18 आर.ई.**	**2018–19 पी.ई.**	**2019–20 ए.ई.**	**2019–20 मे 2018–19 की तुलना मे विकास दर मे % अंक का परिवर्तन (+/-)**
सकल वर्धित मूल्य	6.9	6.6	4.9	–1.7
कृषि और संबद्ध क्षेत्र	5	2.9	2.8	–0.1
उद्योग	5.9	6.9	2.5	–4.4
खनन और उत्खनन	5.1	1.3	1.5	–0.2
विनिर्माण	5.9	6.9	2	–5
बिजली, गैस, पानी, आपूर्ति व अन्य उपयोगिता सेवाएँ	8.6	7	5.4	–1.6
निर्माण	5.6	8.7	3.2	–5.6
सेवाएँ	8.1	7.5	6.9	–0.7
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण	7.8	6.9	5.9	–1
वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएँ	6.2	7.4	6.4	–1.1
सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा संबंधित और अन्य सेवाएँ	11.9	8.6	9.1	–0.5
बाजार मूल्य पर सकल घरेलू मूल्य	7.2	6.8	5	.–1.8

स्रोत–राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

नोट –आर.ई.–संशोधित अनुमान, **पी.ई.**–अनंतिम अनुमान, **ए.ई.**–उन्नत अनुमान

मई तक) का ऋण अधिस्थगन प्रदान किया, इसी के साथ जिन ऋणियों का ऋण वापसी में अच्छा ट्रैक रिकार्ड है उन्हें 3,00,000 तक के ऋण पर 3% ब्याज में छूट भी प्रदान की गयी।[17]

5. उत्पादन एवं उपभोगों पर प्रभाव

लॉकडाउन में उत्पादन कार्यों व परिवहन पर रोक लगने के कारण देश की जी.डी.पी. में बहुत कमी आयी है। यातायात साधनों पर प्रतिबन्ध लगने के कारण कच्चे तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 65 यू0एस0 $ प्रति बैरल से घटकर 18 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर 22 यू.एस. $ प्रति बैरल पर आकर रूकी। इससे भारत के चालू खाते की कमी के कम होने का अनुमान है (जो कि जी.डी.पी. का 1.55% है)।[18] उद्योगों के बन्द होने के कारण जहाँ एक ओर उत्पादन कार्य बन्द हुए वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हुयी। लाखों मजदूरों ने वापस अपने पैतृक गाँवों की तरफ पलायन किया। उत्पादन कम होने से लोगों की व्यक्तिगत आय पर भी प्रभाव पड़ा जिससे व्यय–योग्य आय कम हुई। उपभोग पिछले कुछ वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार है। आवश्यक वस्तुओं के उपभोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा परन्तु अन्य वस्तुएँ प्रभावित रही। उच्च मुद्रास्फीति अर्थिक अनिश्चितता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी चिंताओं के फलस्वरूप उपभोग एवं निवेश के निर्णयों पर दीर्घगामी प्रभाव पड़ेगा।

6. विमानन एवं पर्यटन उद्योग पर प्रभाव

लॉकडाउन के प्रथम चरण में अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विमान संचालन पर प्रतिबन्ध लगने से विमानन उद्योग को अभूतपूर्व क्षति हुई। एक अनुमान के अनुसार वैश्विक स्तर पर विमान यात्रियों से प्राप्त होने वाली आय में लगभग 314 यू.एस. डॉलर की अथवा 2019 से तुलना के आधार पर 55% की कमी आयी है (अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ)। पर्यटन उद्योग में कार्यरत 100 मिलियन से अधिक लोगों के वैश्विक स्तर पर बेरोजगार होने की आशंका है (वर्ल्ड ट्रैवल एण्ड टूरिज्म काउन्सिल)। 2018–19 में लगभग 10 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आये थे जो कि भारतीय सरकार के लिए आय प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण अंग थे।[19] विमानन उद्योग, भारत की जी.डी.पी. में 72 बिलियन यू.एस. डॉलर का भाग रखता है।[20] इस वर्ष की प्रथम तिमाही में इस उद्योग तीव्र गिरावट हुई है। रेलवे की 2019 में जी.डी.पी. में 27.13% बिलियन यू.एस. डॉलर की हिस्सेदारी थी। 21 दिनों के लॉकडाउन के प्रथम चरण में लगभग 7 से 8 लाख करोड़ आय की हानि हुई है।[21] यह कहना गलत नहीं होगा कि कोविड-19 का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव विमानन एवं पर्यटन उद्योग पर ही पड़ा है और इस क्षति से इसे उबरने में अभी कई साल लगेंगे।

7. वित्तीय बाजारों पर प्रभाव

कोविड–19 ने वित्तीय बाजारों (मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार व डेरीवेटिव बाजार) को बहुत नुकसान किया है। विदेशी विनियोजकों में भी विश्वास की कमी आयी है। मार्च, 2020 के प्रारम्भिक दिनों में ही विदेशी पोर्टफोलियों विनियोजकों ने लगभग 15.9 बिलियन डॉलर भारतीय समता बाजार व ऋण बाजार से वापस ले लिया (एन.एस.डी.एल.)।[22] नकदी के इस आगम–निर्गम का प्रवाह प्रतिभूतियों के बाजार मूल्यों पर भी दिखा। 2010 के पश्चात् पहली बार इतना उतार–चढ़ाव दिखा है (**चित्र–4**)।

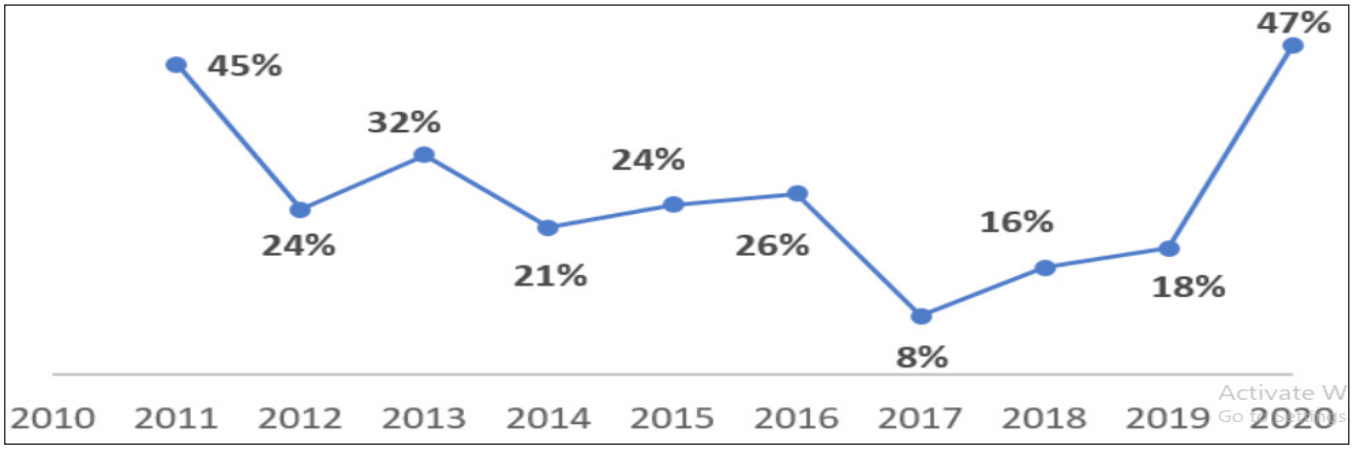

चित्र–4: वार्षिक दिनों का प्रतिशत जब सूचकांक 1% से अधिक बढ़ा या घटा हो
स्त्रोत– बी.एस.ई. (जुलाई 22, 2020 तक के तथ्य)

चित्र–5 में वर्ष 2020 की स्थिति 2017 के समान दिख रही है। 2017 व 2020 में सूचकांक के 1% से अधिक व 1% से कम होने के दिनों का अनुपात क्रमशः 1.33 व 1.32 है जो लगभग बराबर है। परन्तु इन्हीं वर्षों के सूचकांक प्रतिफल देखें तो यह क्रमशः 28% व –9% है जिनमें बहुत अन्तर है। वित्तीय वर्ष 2020 मे कोविड ने प्रतिभूतियों के प्रतिफल पर नकारात्मक प्रभाव डाला जिसने निवेशकों के भरोसे और विश्वास को ध्वस्त कर दिया।

8. संचार माध्यम और मनोरंजन उद्योग पर प्रभाव

कोविड-19 ने भारतीय मनोरंजन जगत पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव डाला है। लॉकडाउन के फलस्वरूप मनोरंजन उद्योग जिसका मूल्य 2019 में 1.8 ट्रिलियन था, उसे 25000 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है (फिक्की के अनुसार)। इस वैश्विक महामारी के भारत में प्रवेश करते ही भारतीय सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए देशव्यापी लॉकडाउन का निर्णय लिया। इसके फलस्वरूप सिनेमा एवं नये टी.वी. ध ाारावाहिकों का प्रसारण भी बन्द हो गया, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने सराहनीय पहल करते हुए दूरदर्शन पर अतिलोकप्रिय धार्मिक धारावाहिक "रामायण" एवं "महाभारत" के पुनः प्रसारण का सुझाव दिया। इसका प्रमुख उद्देश्य इस निष्क्रिय उद्योग में तेजी लाना एवं हतोत्साहित जनमानस में नवीन उर्जा का संचार करना था। अपेक्षानुसार इस पहल ने मनोरंजन जगत में नवीन प्राण डाल दिए। इससे टी.वी. दर्शकों की संख्या में कोरोनाकाल से पूर्व की तुलना में 43% की आशातीत वृद्धि हुई (ब्राडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च काउंसिल)। यह बढ़त प्रसार भारती के विशेष सन्दर्भ में लगभग 40000% की थी। इस प्रकार डी.डी. नेशनल ने 16 अप्रैल, 2020 को रामायण के प्रथम एपिसोड के पुनः प्रसारण मे 77 बिलयन दर्शक संख्या के साथ एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इस सम्बन्ध में किसी भी खेल की नयी स्पर्धा के न होते हुए भी खेल जगत के चैनलो की दर्शक संख्या में 21% की बढ़त, आश्चर्य की बात है (ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च काउंसिल)। इन चैनलों पर भारतीय क्रिकेट टीम की भारी जीत वाले मैचों को दिखाकर जनता को सुखद अनुभूति देने का प्रयास किया गया।[23]

9. स्वास्थ्य क्षेत्र व फार्मास्यूटिकल उद्योग पर प्रभाव

इस क्षेत्र पर कोविड–19 का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं में तेजी से वृद्धि हुई एवं फार्मास्यूटिकल उद्योग में जैनरिक दवाओं (आवश्यक दवा) की बिक्री में भी तेजी आयी है। भारत से विश्व भर में सस्ती एवं उचित मूल्यों पर दवा निर्यात की जाती है। भारत 250 से अधिक अमेरिका फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एवं बिट्रेन के मेडिसिन एवं हेल्थकेयर प्रौडक्टस् रेगूलेटरी एजेन्सी से मान्यता प्राप्त प्लान्ट्स को सहायता प्रदान करता है। भारत का सक्रिय फार्मास्युटिक घटक (ए.पी.आई.), जो कि कोविड–19 से लड़ने के लिये टीके के निर्माण में अतिआवश्यक है, का बाजार 2020 में 6 बिलियन अमेरिकी $ के होने की आशंका है।[24] दवाईयों, टीका व चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती हुई माँग इस व्यवसाय के लिये एक प्रेरक तत्व का काम कर रही है।

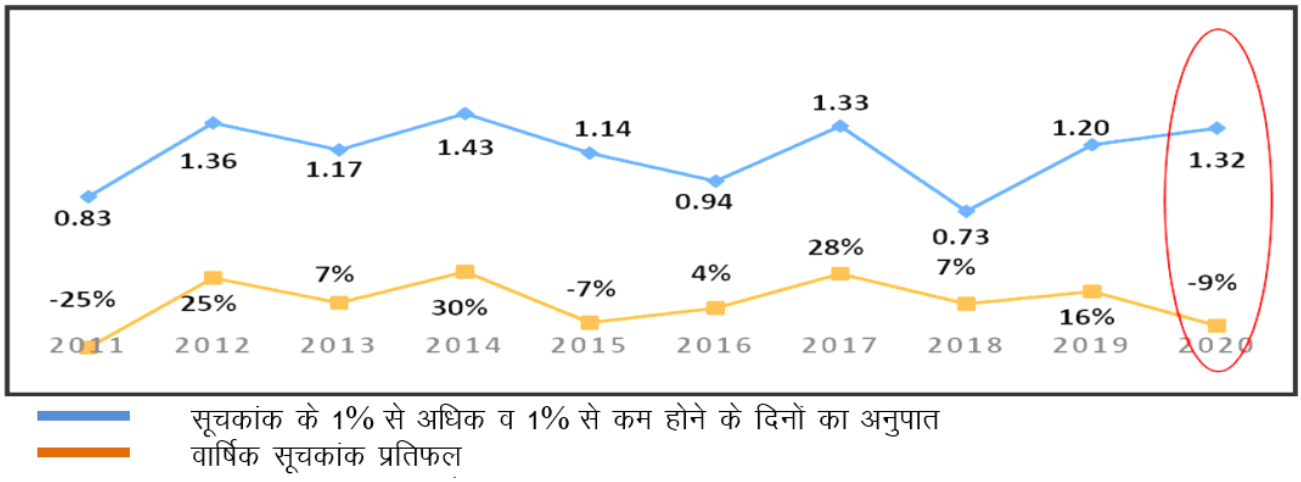

चित्र–5: कोविड–2020 का प्रतिभूति बाजार पर प्रभाव पड़ा
स्रोत– बी.एस.ई. (जुलाई 22, 2020 तक के तथ्य)

10. खुदरा उद्योगों पर प्रभाव

खुदरा उद्योग, जोकि 2019 मे 790 बिलियन यू.एस. $ का था, जी.डी.पी. का लगभग 10% एवं रोजगारों के सृजन में 8% की हिस्सेदारी रखता है। इस उद्योग के ऑनलाइन क्षेत्र मे लॉकडाउन काल में अत्यन्त प्रगति देखने को मिली है।[25] इस लॉकडाउन में संगठित खुदरा क्षेत्र को लगभग 90,000 करोड़ के नुकसान के बाद, खुदरा व्यापारी बाजार में बने रहने के लिए रणनीतियाँ बना रहे हैं।[26] फ्यूचर ग्रुप, स्पेंसर रिटेल, मेट्रो कैश एंड कैरी और वॉलमार्ट के बेस्ट प्राइस सहित बड़े प्रारूप वाले ऑफलाइन खुदरा व्यापारी व थोक विक्रेताओं ने ग्राहकों को ऑनलाइन सेवा देने के प्रयासों को आगे बढ़ाया है, जो एक राष्ट्र तालाबंदी के दौरान सामान और किराने का सामान वितरित करने के लिए ओमनी चैनल मॉडल का निर्माण कर रहे हैं।[27] इस क्रम में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ''एम.एस.एम.ई. प्रेरणा'' कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म, छोटे व मझोले उद्योगों को ऑनलाइन व्यापार के लिए इण्डियन बैंक के माध्यम से वित्तीय प्रेरणा देने की घोषणा की है। इस समय ऑनलाइन खुदरा बाजार में लगभग 30% की वृद्धि हुई (नेशनल इन्वेस्टमेन्ट प्रोमोशन एण्ड फैसीलिसेशन एजेन्सी, 2020)।[28] यह एक प्रकार से अन्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति के रूप में देखा जा सकता है।

11. रोजगारों पर प्रभाव

प्रवासी मजदूरों के पलायन ने बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की। इन प्रवासी मजदूरों की समस्या ने कहीं न कहीं स्वरोजगार, साहसी, उद्यमिता एवं सूक्ष्म, छोटे व मझोले व्यवसायों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है। अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ ने अपनी रिपोर्ट में इस महामारी को द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की सबसे खराब वैश्विक संकट की संज्ञा दी है। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत लगभग 400 मिलियन व्यक्तियों (कुल कार्यशील जनसंख्या का 76.2%) के सामने महामारी ने बेरोजगारी, निर्धनता व भुखमरी जैसी भीषण समस्या खड़ी कर दी है। यह परिस्थिति विश्व में 195 मिलियन पूर्णकालिक रोजगार अथवा कार्यशील घण्टों का 6.7% का नुकसान कर रही है (आई.एल. ओ.)।[29] लॉकडाउन मे कई व्यक्तियों ने अपना रोजगार खो दिया, या वेतन कम कर दिया गया या कम कुशलता वाले रोजगारों में जाने को विवश होना पड़ा। इस सम्बन्ध में जन साहस (गैर–लाभ संस्था) द्वारा 3196 प्रवासी मजदूरों पर किये गये सर्वेक्षण के तथ्य इस प्रकार है[30]–

12. शिक्षा के क्षेत्र पर प्रभाव–

लॉकडाउन में शिक्षण संस्थाओं को बंद रखने से भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब रू. 2.93 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। यह नुकसान दक्षिण एशिया क्षेत्र में कुल 6,220 करोड़ डॉलर का है। यदि हालात और बिगड़े तो यह नुकसान 8,880 करोड़ डॉलर तक बढ़ सकता है। इसमें भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है (बीटन और ब्रोकनः इनफॉर्मेलिटी एण्ड कोविड–19 इन साउथ एशिया)। विश्व बैंक की ''लर्निंग–एडजेस्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग''(लेज) प्रणाली के अन्तर्गत दावा है कि दक्षिण एशिया के बच्चे बड़े होकर जब रोजगार के काबिल होंगे तो वह अपने जीवनकाल में लगभग 4400 डॉलर कम कमा सकेंगे। प्रति व्यक्ति आय में तकरीबन 5% का नुकसान आंका गया है।[31]

13. सुझाव व निष्कर्ष

सारणी–5: कोविड–19 का प्रवासी मजदूरों पर प्रभाव

दैनिक मजदूरी		समस्यायें		सरकारी सुविधायें	
रू0 200 से 400	55%	कार्य न मिलना	83-1%	आधार कार्ड न होना	99-2%
रू0 400 से 600	39%	राशन न मिलना	80-8%	जन–धन खाता या खाता न होना	86-7%
रू0 600 से अधिक (न्यूनतम मजदूरी दर के लगभग बराबर)	4%	गांवो को वापस जाने मे असमर्थ	47-8%	राशन कार्ड न होना	61-7%
		बीमार	15-1%	बी.पी.एल. कार्ड न होना	23-7%
		शादी करने में कठिनाई	8-7%		
		समस्या नहीं पता	5%		
		कोई समस्या नहीं	3-5%		
		शिक्षा पर खर्चे के लिये नहीं	2-4%		

स्त्रोत– जन साहस सर्वेक्षण

कोविड–19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है परन्तु जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार इस विषम परिस्थिति को भी एक अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। इस महामारी ने विश्व की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है व वैश्विक स्तर पर यह सभी राष्ट्रों के लिये संकट का समय है। विश्व व्यापार संघ ने वर्ष 2020 में वैश्विक व्यापार (वस्तुओं का व्यापार) में लगभग 13% से 32% की कमी का अनुमान लगाया है। भारत को सबसे बड़ा झटका चीन से व्यापार बंदी से लगा है। चीन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारी राष्ट्र है।

चित्र–6 में अगर देखें तो चीन से आयतित माल पर भारत की निर्भरता कहीं अधिक है। भारत को इस आपदा को अवसर मे परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। यह समय भारत के लिये एक पूर्ण आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने का सुअवसर है। भौगोलिक सीमाओं के सील होने से आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, फलस्वरूप अनेक वस्तुओं का आयात प्रतिस्थापन करने के उद्देश्य से उनका उत्पादन भारत में ही किया जा रहा है। यह एक अच्छी पहल है जो एक ओर राष्ट्र की सकल घरेलू आय को बढ़ायेगा, वहीं दूसरी ओर रोजगारों के नये अवसरों को भी सुनिश्चित करेगा। परन्तु यह सुझाव दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सुझाव इस प्रकार है–

1. भारत अपनी सकल घरेलू आय का मात्र 3.5% ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगाता है जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं जैसे बाजील (9%) व रूस (6.5%) की तुलना में बहुत कम है। इस मद पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करने की आवश्यकता है।[32]
2. इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने रू. 1.7 लाख करोड का प्रोत्साहन पैकेज दिया है जो कि सकल घरेलू आय का मात्र 0.8% है। भारत, अमेरिका के राहत पैकेज (जी.डी.पी. का 10%) की बराबरी नहीं कर सकता परन्तु चीन के (जी.डी.पी. का 2.5%) पैकेज तक इसे पहुँचा सकता है।[33]
3. कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। भारत सरकार ने अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत किसानों के खातों में सीधे रू. 2000 हस्तान्तिरत किये जिससे रू. 17,380 करोड़ की धनराशि से लगभग 8.69 करोड किसान परिवारों तक सहायता पहुँचायी गयी। परन्तु यह धनराशि कृषि क्षेत्र को राहत पहुँचाने के लिए बहुत कम है इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।[34]
4. जनता पर बोझ कम करने के उद्देश्य से सरकार ने वयस्क नागरिकों, विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांगों के खातो में रू. 1000 एवं महिलाओं के खातों में जन–धन कार्यक्रम के अन्तर्गत रू. 500 हस्तान्तरित किया। यह हस्तान्तरण प्रतिमाह तीन माह तक किया गया (वित्तीय सेवा विभाग)। यह धनराशि इस संकट काल में जीविका चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इण्डियन सोसायटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स द्वारा यह धनराशि न्यूनतम रूप में रू0 6000 प्रतिमाह का सुझाव दिया गया है।[35]
5. निर्माण उद्योग जो जी.डी.पी. का 8% भाग है, इस संकट काल मे मंदी झेल रहा है। इस संदर्भ मे केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को राहत कोष के उपयोग का सुझाव दिया है। इस क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के रोजगार की भी समस्या जटिल है।[36]
6. इस विषय में सरकार को निर्धनों को दी जाने वाली सुविधाओं में औपचारिकताओं में ढील देने की आवश्यकता है जैसे–बिना राशन कार्ड वाले मजदूरों को भी राशन उपलब्ध कराना।
7. मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी रू. 182 से बढ़ाकर रू. 202 की गयी जिससे लगभग 5 करोड़ परिवारों तक मदद पहुँचायी गयी।[37]

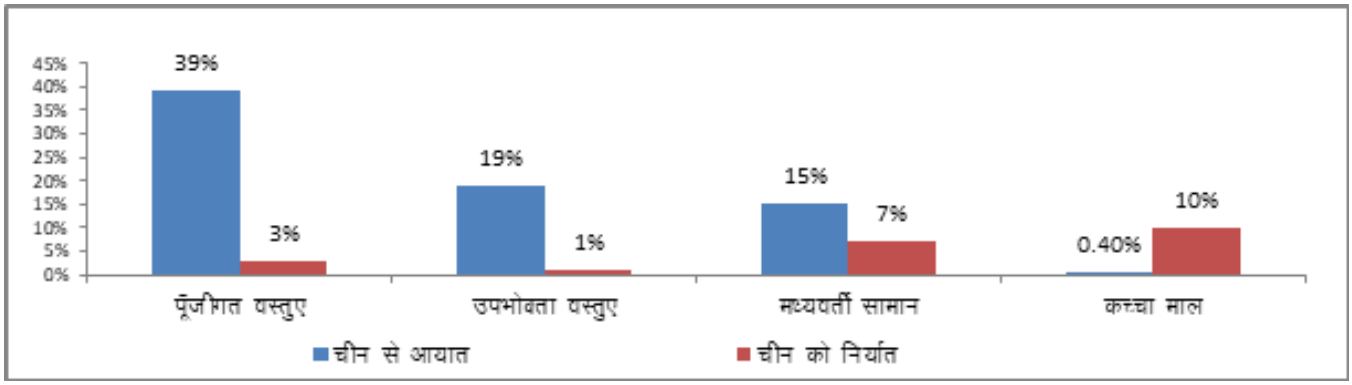

चित्र–6: व्यापार के लिये चीन पर भारत की निर्भरता (2014–2018 का औसत व्यापार)
स्रोत– टेक्नोलॉजी पेनोरमा

मनरेगा के तहत पलायन किये हुए मजदूरों के लिए उत्पादक सम्पत्ति की व्यवस्था करवानी चाहिये।

8. कुछ क्षेत्रों में भारत अग्रणी उत्पादक की भूमिका निभा रहा है (जैसे–पी.पी.ई. किट, दवाओं व अन्य जरूरी वस्तुओं का निर्यात इत्यादि। सरकार को इन वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए।
9. इस सम्बन्ध में डब्ल.एच.ओ. को अपने बजट (जो कि अभी मात्र 4.4 बिलियन $ का है) को बढ़ाने की आवश्यकता है और इसका प्रयोग विशेषकर निम्न विकसित राष्ट्रों के उत्थान में करने की आवश्यकता है (जागरूकता कार्यक्रम, टीके के शोध, आवश्यक मेडिकल आपूर्ति, टेस्टिंग किट, स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रचर इत्यादि की मद पर)।[38]
10. आर्थिक संकट अपराध को भी जन्म देते हैं। अतः केन्द्र व राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था को चाकचौबंद करने की आवश्यकता है।
11. सरकार को आपूर्ति **श्रृंखला** को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इस सन्दर्भ में फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों एवं स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

इन सब सुझावों को अंगीकृत करके सरकार संकट काल में अर्थव्यवस्था में स्थायित्व प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है। परन्तु कोविड–19 का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर लम्बे समय तक दृष्टिगोचर होगा। **राष्ट्रीय** रेटिंग एजेन्सी क्रिसिल के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था पर इस महामारी का प्रभाव ''V'' आकार का होगा जो सदैव के लिये एक स्थायी चिह्न छोड़ जायेगा।[39] इन प्रभावों का दीर्घकालीन प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

सन्दर्भ

1. https://news.cgtn.com/news/2020-07-11/Is-overpopulation-to-blame-for-pandemics--S2IImZOdPO/index.html
2. covid19.who.int/coronavirus/dashboard
3. https://mohfw.gov.in/
4. https://www.euronews.com/2020/04/02/coronavirus-in-europe-spain-s-death-toll-hits-10-000-after-record-950-new-deaths-in-24-hou
5. http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/
6. एमिड् कोविड–19 इम्पैक्ट, इंडियन इकोनॉमी फोरकास्ट टू कॉन्ट्रेक्ट 5.9% इन 2020, यू0एन0, द हिन्दू, दिनांकः 23.09.2020
7. फिच स्लैशेस जी.डी.पी. एस्टीमेट टू 0.8%, मूडीज टू 0.2%, द इकोनॉमिक टाइम्स, दिनांकः 28.04.2020।
8. कोरोना वायरस क्राइसिसः ₹ 10 लाख करोड़ स्टिमुलस नीड ऑफ द ऑवर, एक्सपर्टस एस्टीमेट, द हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांकः 10.04.2020।
9. आई.एम.एफ. 1.9% ग्रोथ प्रेडिक्शन फॉर इंडिया ल्यूडिक्रश, एक्च्युल फिगर कुड बी निगेटिव, द वायर, दिनांकः 20.04.2020।
10. स्टीपर कॉन्ट्रेक्शन इन फाइनेंशियल इयर 21 जी.डी.पी.: इकरा रिवाइजेज फोरकास्ट डाउनवर्डस्, द इकोनॉमिक टाइम्स, दिनांकः 28.09.2020।
11. इंडिया जी.डी.पी. ग्रोथ कॉन्ट्रेक्टस् 23.9% : व्हाट इज द इकोनॉमिक्स बिहाइंड द मैथ?, द इंडियन एक्सप्रेस, दिनांकः 06.09.2020।
12. वर्ल्ड बैंक ऐस्टीमेट्स इंडियाज जी.डी.पी. टू प्लन्ज 9.6% इन 2020.2021, शार्पर दैन जून फोरकास्ट ऑफ 3.2% कॉन्ट्रेक्शन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिनांकः 08.10.2020।
13. एग्रीकल्चर जी.वी.ए. ग्रोथ इन फायनेंशियल इयर 21 सीन एट 2.5%, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दिनांकः 05.06.2020।
14. अवर फारमर्स मेड अप टू 80% लॉसेस इन द लॉकडाउन, सेज हॉर्टीकल्चर स्टार्ट अप आई.एन.आई. फार्मस्, द इकोनॉमिक टाइम्स, दिनांकः 30.04.2020।
15. लॉकडाउन ब्लूजः फ्लॉवर बिजिनेस इन कर्नाटका विलट्स, रू0 360 करोड़ लॉस हिट्स सेक्टर, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, दिनांकः 02.06.2020।
16. मूवमेंट ऑफ इसेंशियल गुड्स हिट बाय डिस्रप्शन्स, द हिन्दू, दिनांकः 02.04.2020।
17. आर0बी0आई0 ऐक्सटेंडस लोन रिपेमैंट मोरेटोरियम बाय थ्री मंथ्स, द हिन्दू, दिनांकः 22.05.2020।
18. डब्ल्यू.टी.आई. ऑयल फाल्स टू $25 ए बैरल फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 2002, द इकोनॉमिक टाइम्स, दिनांकः 18.03.2020।
19. एयरलाइन रेवेन्यूज टू नोजडाइव बाय 55% इन 2020: आई.ए.टी.ए., द इकोनॉमिक टाइम्स, दिनांकः 15.04.2020।
20. https://www.investindia.gov.in/sector/aviation
21. वर्ल्ड बिगेस्ट लॉकडाउन मे हैव कॉस्ट रू0 7–8 लाख करोड़ टू इंडियन इकोनॉमी, द इकोनॉमिक टाईम्स, दिनांकः 13.04.2020।
22. फियरफुल एफपीआईज मार्च आउट ऑफ इंडियन मार्केट्स, पुल आउट ए रिकॉर्ड $15.9 बिलियन, द इकोनॉमिक टाईम्स, दिनांकः 01.04.2020।

23. इंडिया रिकॉर्डस् हाइयेस्ट टीवी कंजम्पशन इन ंवीक विद टोटल टाइम स्पेंट ऑफ 1.27 ट्रिलियन मिनट्स, द इकोनॉमिक टाईम्स, दिनांकः 09.04. 2020।

24. द राइज ऑफ ए.पी.आई. बैरन्स, बिजिनेस वर्ल्ड, दिनांकः 08.10.2020।

25. कोरोना वायरस इंपैक्ट ऑन इंडियाज रिटेल सेक्टर, द इकोनॉमिक टाईम्स, दिनांकः 14.04.2020।

26. द फ्यूचर ऑफ इंडियन रिटेल पोस्ट–कोविड, द हिन्दू, दिनांकः 15.04.2020।

27. कोविड–19 क्राइसिस इज पुशिंग बिग ऑफलाइन रिटेलर्स ऑनलाइन, द इकोनॉमिक टाईम्स, दिनांकः 15.04.2020।

28. https://www.investindia.gov.in/searchresults?term=online%20retail%20increased%20by%2030%20in%20covid%20era

29. रैपिड एसेसमेंट ऑफ द इंपैक्ट ऑफ कोविड–19 क्राइसिस ऑन एम्लॉयमेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन, दिनांकः जून 2020।

30. कोविड–19 रिलीफ रेस्पांस स्टोरीज ऑफ रिसायलेंस एण्ड होप, जन साहस–2020।

31. लॉकडाउन का असरः बंद स्कूलों से भारत को 3 लाख करोड़ का नुकसान, दैनिक जागरण, दिनांकः अक्टूबर 13, 2020।

32. https://thewire.in/health/health-budget-figures-tell-a-sick-story

33. The Economic Times (March 27, 2020), FM Nirmala Sitharaman announces Rs 1.7 lakh crore relief package for poor

34. The Economic Times (March 26, 2020), Govt to transfer Rs 2,000 under PM-KISAN scheme to 8.69 crore farmers in April 1st week

35. Business Today (March 26, 2020), Coronavirus relief aid: Who gets how much direct cash transfer?

36. https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=16589

37. The Hindu (22 March, 2020) Coronavirus:Lockdown hits NREGA workers hard

38. http://www9.who.int/bulletin/volumes/91/7/13-010713/en/

39. CRISIL (May 26, 2020), Minus Five India GDP growth outlook for fiscal 2021